NOTIFICATIONS UNDER MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969 AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL WAKF COUNCIL FOR 1979-80

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE, AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR) : I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under subsection (3) of section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:—

(i) G.S.R. 1289 published in Gazette of India dated the 20th December, 1980 containing Corrigendum to Notification No. G.S.R. 448(E) dated the 25th July, 1980.

(ii) The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members and Staff) Third Amendment Rules, 1980, published in Notification No. G.S.R. 3, in Gazette of India dated 3rd January, 1981.

[*Placed in Library. See* No. LT-1990/81]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wakf Council for the year 1979-80 along with Audited Accounts.

[*Placed in Library See.* No. LT-1980/81]

12-05 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) AMALGAMATION OF CHITTARANJAN NATIONAL CANCER RESEARCH CENTRE AND CHITTARANJAN CANCER HOSPITAL, CALCUTTA.

DR. SARADISH ROY (BOLPUR) : Sir, a proposal for the merger of Chittaranjan National Cancer Research Centre and Chittaranjan Cancer Hospital, Calcutta with a view to set up a Regional Cancer Centre for Eastern India, has been accepted in principle long before but not implemented so far. Several meetings were held between the State Governmet of West Bengal and Central Ministry of Health on this proposal. Amalgamation of the Research Centre and the Hospital for Research and Treatment of Cancer in Eastern India is necessary and this issue hould be settled expeditiously.

Under there circumstance, I urge upon the Government to give directions to the Ministry for finalising the amalgamation of the two institutions immediately.

I also demand that the Minister make a statement thereon.

(ii) DISPUTE BETWEEN U.P. AND BIHAR RE: ALLEGED OCCUPATION OF CERTAIN BIHAR LANDS BY U.P. FARMERS.

PROF. K.K. TEWARY (Buxar) : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I wish to raise the following matter of urgent public importance under Rule 377 :

Sir, there is a long-standing boundary dispute between U.P. and Bihar due to the constantly changing mid-stream of the river Ganga affecting large areas in Ballia and Bhojpur districts of the respective States. Affected farmers of these districts have taken this dispute to Courts and there have been a series of Litigations. The dispute has also led to violent clashes and claimed many lives in the recent years. The entire region is in the grip of unprecedented tension following forcible occupation of thousands of acres of Diara land of Bihar farmers by U.P. farmers supported by the authorities of U.P. Especially in view of the onset of harvesting of the Rabi crops, the prevailing tension is bound to lead to large scale violence and bloodshed.

I request the Central Government to intervene and restore these lands to the Bihar farmers to whom it really belongs.

(iii) DEVELOPMENT OF COLACHEL PART IN TAMIL NADU.

SHRI N. DENNIS (Nagercoil) : Mr. Speaker, with your permission, I wish to raise the following matter of urgent public importace under Rule 377. Calatchel harbour, which is in the West Coast of Tamil Nadu, has to be developed at least as a Minor Port. This is the only Harbour for Tamil Nadu in the West Coast. This is an historical ancient harbour which had regualr trade with the neighbouring countries, such as Sri Lanka, Middle-East and also Continental countries till recently. But it has so far not developed and its previous importance is vanishing. If this harbour is developed, trade and commerce there would be revived. Marine food-stuffs, mineral rare-earths, fibre, coir products and other products of this area could be exported conveniently. As the other Ports from this area are situated far away, now the export potentiality is retarded and the people of this area suffer economically. So, I request that Government may be pleased to take early steps for the development of Colochel Port at least as a Minor Port. Thank you.

(iv) DEVELOPMENT OF CERTAIN CANTONMENT AREAS IN HIMACHAL PRADESH.

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, शिमला तथा सिरमौर में डगशाई, कसौली

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

जतोग, सबाठू तथा नाहन आदि छावनियां स्थित हैं । ये छावनियां भूतपूर्व अंग्रेजी शासन के समय से चली आ रही हैं । पहले इन छावनियों के विकास तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले साधारण नागरिकों की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

इन स्थानों की जलवायु उत्तम होने के कारण गर्मियों के मौसम में काफी मात्रा में पर्यटक यहां आते हैं जिससे वहां के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचता था । परन्तु वर्तमान में इन छावनियों की देखभाल तथा विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसका परिणाम यह है कि वहां की सड़कें टूट फूट रही हैं, सफाई का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है, पीने के पानी के अभाव के कारण न केवल वहां के नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि पर्यटकों को भी भारी असुविधा हो रही है ।

धर्मपुर से सबाठू तक की सड़क जो सेना के अधीन है उसकी बुरी हालत है । इस सड़क को चौड़ा करने तथा इसकी मरम्मत करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस सड़क पर भारी यातायात होने के कारण नित्य प्रति कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है । क्योंकि यह सड़क राज्य सरकार के अधीन नहीं है इसलिए वह भी इसकी मरम्मत नहीं करती है । अतः यह आवश्यक है कि यातायात को ध्यान में रखते हुए तुरन्त इस सड़क को चौड़ा करने की व्यवस्था की जाए ।

इसी प्रकार इन छावनियों में पीने के पानी की अतिरिक्त व्यवस्था का किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

इन छावनियों में काफी मात्रा में बंजर भूमि पड़ी हुई है जो इस समय किसी भी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है । इस भूमि को उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीनों में बांट दिया जाना चाहिए ताकि इनका विकास हो सके ।

मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त विषयों पर तुरन्त ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

(v) ENHANCEMENT OF RATES AND INADEQUATE SUPPLY OF WATER AND ELECTRICITY TO FARMERS

श्री मणीराम बागड़ी (हिसार) : यही वह मौसम है जबकि किसानों को अपने खेतों की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि उनकी फसल को कोई नुकसान न पहुंचे । हरियाणा और अन्य राज्यों ने गेहूं की फसल में काफी सफलता प्राप्त की है और वे इसको पूर्ति देश के सभी भागों को कर रहे हैं । यह बहुत खेद की बात है कि ऐसे समय पर जबकि पम्प सेटों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, अधिकारियों ने बिजली की दरों में अनुचित बढ़ोतरी कर दी है । यह वृद्धि अनुचित, अवांछित और अभूतपूर्व है । स्वाभाविक है कि इसमें बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हुआ है । मैं स्वयं भिवानी जिले के लोहारू गया था ताकि वहां जाकर सही सही जानकारी प्राप्त कर सकूं । मैं यह पूरी तरह से मानता हूं कि किसानों की मांगें न्यायसंगत और उचित हैं और यह बात बहुत आवश्यक है कि कम से कम एक महीने के लिए दिन रात बिजली की सप्लाई होती रहे और उनकी दर में कोई वृद्धि न हो ताकि किसान गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर सके । चूंकि इससे किसानों के हितों की नुकसान